इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 11 जून 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
विदेशी मुद्रा विनिमय----------5
सूक्ष्मवित्त -- ----------5
पण्य (जिंस) बाज़ार ----------6
अर्थव्यवस्था ----------6
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ----------7
आईआईबीएफ की गतिविधियां----------7
संस्थान समाचार----------8
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति की समीक्षा - 3 मई 2011

मौद्रिक उपाय

- पुनर्खरीद (रेपो) दर तात्कालिक प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ा कर 7.25 % की गई।
- प्रत्यावर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर तात्कालिक प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ा कर 6.25 % की गई।
- बचत बैंक की ब्याज दर 3.5 % से तात्कालिक प्रभाव से बढ़ा कर 4 % की गई।
- बैंकों के लिए 7 मई से 8.25 % की सीमान्त स्थायी (Marginal Standing) सुविधा लागू की गई।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 200 आधार अंकों के गलियारे (corridor) वाली एकल दर प्रणाली अपनाई।

वृद्धि / मुद्रास्फीति से सम्बन्धित अनुमान

- चालू वित्तीय वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के 8% रहने का अनुमान।
- मार्च के अंत तक मुद्रास्फीति की दर 6% रहने का अनुमान।
- मुद्रा आपूर्ति दर से सम्बन्धित वृद्धि के 16 % रहने का अनुमान।
- ऋण वृद्धि के 19 % रहने का अनुमान।

- जमाराशियों में 17 % की वृद्धि होने की आशा।

- चालू खाते के घाटे कें वित्तीय वर्ष 10 के 2.8 % के मुकाबले वित्तीय वर्ष 11 में घट कर 2.5 % रहने की आशा।

बैंकिंग विनियमन

- बैंकों से जनवरी 2013 से बासेल- III की शुरूआत करने हेतु कहा गया।

- अशोध्य ऋणों से सम्बन्धित प्रावधानीकरण बढ़ाया गया।

- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) को बैंक ऋण 1 अप्रैल से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत।

मुख्य घटनाएं

वित्तीय क्षेत्र में नियमों को पुनर्रचित करने हेतु वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग ने रूपरेखा निर्धारित की

वित्तीय क्षेत्र से सम्बन्धित विधानों को पुनर्रचित करने के एक अभियान के तहत वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) ने उक्त क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्रों, यथा - प्रतिभूति, बीमा, पेंशन एवं बैंकिंग में कार्य दलों का गठन किया है। पेंशन निधि के विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री डी. स्वरूप बीमा और पेंशन वाले समूह के प्रमुख हैं। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग प्रत्येक कार्य दल की सहायता करने के लिए वित्त एवं अर्थशास्त्र में परामर्शदाताओं, कानूनी सलाहकारों और विशेषज्ञों की नियुक्ति कर रहा है। इन कार्य दलों द्वारा जून से कार्य आरंभ कर दिए जाने तथा आयोग को निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा हैं।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) संपदा प्रबन्धन विनियमों को सुदृढ़ बनाएगी

संपदा प्रबन्धकों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ियों की घटनाओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्तीय विनियामकों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय पैनल ने उक्त क्षेत्र को बेहतर ढंग से विनियमित किए जाने के मुद्दे पर सहमति व्यक्त की है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) ने वित्तीय समूहों के पर्यवेक्षण तथा काउंटर पर खरीदी-बेची जाने वाली व्युत्पन्नी बाज़ार से

सम्बन्धित रिपोर्टिंग के लिए संपदा प्रबन्धन के कार्यकलापों के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सुदृढ़ व्यवस्था निर्मित किए जाने हेतु एक संस्थागत व्यवस्था लागू किए जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दरें बढ़ाने हेतु तैयार

भारतीय रिज़र्व बैंक इस वित्तीय वर्ष के अधिकांश भाग में ब्याज दरें बढ़ाने के लिए तत्पर है, क्योंकि वह कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की वैश्विक कीमतों की अधिकता को मुद्रास्फीति को उसकी सहूलियत के स्तर से अधिक पर ले जाने तथा वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में देखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का मानना है कि निरंतर मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में मध्यावधि वृद्धि को स्थिर रखने के उद्देश्य से मुद्रास्फीति-विरोधी मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है। स्थूल-आर्थिक एवं मौद्रिक विकास 2010-11 पर उसकी रिपोर्ट की अन्तर्निहित विषय-वस्तु वृद्धि को गति को बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति से निपटना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिपोर्टिंग शुक्रवारों को दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा समाप्त की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 मई से रिपोर्टिंग शुक्रवारों को दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) समाप्त कर दी है। सीमान्त स्थायी सुविधा और मौद्रिक नीति की आशोधित परिचालन कार्यविधि को लागू किए जाने के बाद उक्त सुविधा समाप्त कर दी गई है।

निदेशकों को विनियामक के ध्यान में प्रतिकूल रूप से आने के ब्योरे देना चाहिए : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि निदेशकों और उस पद के अभ्यर्थियों को, जब तक कि मामले का उनके पक्ष में निपटारा न हो गया हो, ऐसी घटनाओं के ब्योरे उपलब्ध कराने होंगे, जहां वे विनियामक निकाय के ध्यान में प्रतिकूल रूप से आए हों।

25 लाख रुपये के गृह ऋण अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार

शहरी क्षेत्रों में निवासीय सम्पत्तियों की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकृत किए जाने की पात्र बनने के लिए आवास ऋण की सीमा को मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर दिया है।

अल्पावधिक निधि समस्याओं से निपटनें में बैंकों की सहायता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने खिड़की खोली

वार्षिक ऋण नीति में की गई घोषणा के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने अल्पावधिक चलनिधि समस्याओं से निपटनें में बैंकों की सहायता करने के लिए सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) से सम्बन्धित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार कोई बैंक सीमांत स्थायी सुविधा के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से अपनी कुल जमाराशियों के 1 % तक की राशि ऐसी दर पर उधार ले सकता है, जो अल्पावधिक उधार (पुनर्खरीद) दर से 100 आधार अंक अधिक हो। वर्तमान में पुनर्खरीद (रेपो) दर 7.25 % है। इस प्रकार सीमांत स्थायी सुविधा के तहत प्रभारित की जाने वाली दर 8.25 % होगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को कृषि क्षेत्र में प्रदत्त ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का दर्जा पा सकते हैं

सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक से ऐसी अपेक्षाकृत छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, जो व्यापक तौर पर कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को उधार प्रदान करती हैं, प्रदत्त बैंक ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का दर्जा प्रदान करने हेतु कह सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उधार देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर उन्हें बैंकों की प्राथमिकता सूची से निकाल दिया है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने कुल अग्रिमों का 40 % कृषि, लघु एवं मध्यम उद्यमों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा कमजोर वर्गों सहित 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' को प्रदान करें। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, जिन्हें वर्तमान में वित्तीयन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है, ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित सरकार के एक भिन्न अंग माने जाने हेतु निवेदन किया है। हालांकि, बैंकों का यह मानना है कि विनियम मे होने वाले किसी भी परिवर्तन से उनके प्राथमिकता प्राप्त संविभाग के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने खज़ाना बिल कार्यक्रम संशोधित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में जारी किए जाने वाले खज़ाना बिलों का कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। अब सरकार जून, 2011 तक इसके पूर्व निर्धारित 7,000 करोड़ की तुलना में प्रति सप्ताह 11,000 करोड़ रुपये उधार लेगी। कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा भारी मात्रा में वापसियां जारी किए जाने के कारण नकदी की स्थिति में आए अस्थायी असंतुलन के आधार पर उद्भूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आशोधित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने काउंटर पर खरीदी-बेची जाने वाली विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों के उपयोग से सम्बन्धित पात्रता मानदंड संशोधित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिम प्रबन्धन परंपराओं का कायापलट करने के लिए काउंटर पर खरीदी-बेची जाने वाली (OTC) विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों (derivatives) के प्रयोक्ताओं के पात्रता मानदंडों को संशोधित कर दिया है। तदनुसार, साझे खजाने और समेकित तुलन पत्र वाली सूचीबद्ध कम्पनियों, और उनकी सहायक कम्पनियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगी कम्पनियों अथवा न्यूनतम 200 करोड़ रुपये की निवल हैसियत वाली गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों को काउंटर पर खरीदी-बेची जाने वाली विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों के उपयोग की अनुमति होगी। पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों में न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की निवल हैसियत वाली गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों को काउंटर पर खरीदी-बेची जाने वाली विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों का उपयोग करने की अनुमति थी। स्पष्टत: भारतीय रिज़र्व बैंक संभाव्य जोखिमों को देखते हुए केवल उन्हीं कम्पनियों को चाहता है, जो काउंटर पर खरीदी-बेची जाने वाली विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों के बाज़ार में सहभागिता करने की स्थिति में हों।

विदेशी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अनुपालन अवश्य सुनिश्चित करना होगा : भारतीय रिज़र्व बैंक

देश में कार्यरत विदेशी बैंकों पर अपने विनियमनों को कठोर बनाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEOs) से अनुपालन प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह मत व्यक्त किया है कि मूल बैंक की शाखाओं के रूप में भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के परिचालनों के बारे में उनके अनुपालन के लिए सामान्यतया निरीक्षणों और लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की जांच एवं समीक्षा करने से सम्बन्धित उत्तरदायित्व वाली अलग से किसी लेखा-परीक्षा समिति की व्यवस्था नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के लिए नियंत्रक कम्पनी मॉडेल का सुझाव दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त और उसकी (भारतीय रिज़र्व बैंक की) उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता वाले एक कार्यदल ने यह सुझाव दिया है कि सभी बड़े वित्तीय समूहों को, चाहे उनके पास बैंक मौजूद हो अथवा नहीं, नियंत्रक कम्पनी वाला मॉडेल अंगीकृत करना चाहिए। सभी बैंकों और बीमा कम्पनियों को जब कभी उन्हें लाइसेंस प्रदान किए जाएं, अनिवार्य रूप से वित्तीय नियंत्रक कम्पनी (FHC) ढांचे के तहत परिचालन करना आवश्यक कर दिया जाना चाहिए। उक्त कार्यदल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस व्यवस्था में बैंकिंग वित्तीय नियंत्रक कम्पनियां और गैर-बैंकिंग नियंत्रक कम्पनियां हो सकती हैं। दूसरी ओर समूह के भीतर बैंक की मौजूदगी वाले सभी अभिज्ञात वित्तीय समूहों के लिए भी एक समयबद्ध विधि से वित्तीय नियंत्रक कम्पनी वाले मॉडेल में परिवर्तित होना आवश्यक होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण चूक अदला-बदली से सम्बन्धित मानदंड पुनर्संरचित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनर्संरचना को एक ऐसी अनुमोदित घटना (अर्थात् इसके पूर्व सहमत वित्तीय दायित्व से सम्बन्धित चूक) के रूप में अनुमति प्रदान की है, जिसे ऋण चूक अदला-बदली (swaps) संविदाओं द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। यह मुहिम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे समय में आरंभ की गई है जब बैंकिंग प्रणाली में अशोध्य ऋण से सम्बन्धित समस्याएं क्रमिक रूप से बढ़ती लग रही हैं। यह वैश्विक स्तर पर मालों एवं सेवाओं की द्रुत गति से बढ़ती मांग, बढ़ती निविष्टि लागतों तथा बढ़ती ब्याज दरों के कारण है। कारपोरेट बॉण्डों के मामले में ऋण चूक अदला-बदली (CDS) से सम्बन्धित अपने दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि ऋण घटना में पुनर्संरचना व्यवस्था और कारपोरेट बॉण्ड पुनर्संरचना का समावेश होगा।

बैंक भारतीय निक्षेपागार रसीदों पर ऋण नहीं प्रदान कर सकते : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक विदेशी कम्पनियों द्वारा जारी भारतीय निक्षेपागार रसीदों (IDRs) पर ऋण नहीं प्रदान कर सकते। भारतीय निक्षेपागार रसीद किसी भारतीय निक्षेपागार द्वारा जारीकर्ता विदेशी कम्पनी की अन्तर्निहित इक्विटी के समक्ष निक्षेपागार रसीद के रूप में सृजित रुपये में मूल्यवर्गित होती है। यह अमरीकी अथवा वैश्विक निक्षेपागार रसीद (ADR/GDR) जैसी ही होती है, जिसमें भारतीय कम्पनियां विदेशों में संसाधन जुटाती हैं। भारतीय निक्षेपागार रसीदें विदेशी कम्पनियों को भारत से भी वैसा ही करने में समर्थ बनाती हैं तथा वे देश के शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध होती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से पोर्टफोलियो प्रबन्धन के ब्योरे उपलब्ध कराने हेतु कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पोर्टफोलियो प्रबन्धन सेवाओं के ब्योरे उपलब्ध कराने हेतु कहा है। इसके पूर्व वित्तीय सेवा विकास आयोग (FSDC) द्वारा संपदा प्रबन्ध सेवाएं प्रदान करने में बैंकों और दलाली गृहों द्वारा अपनाई जाने वाली मौजूदा प्रथाओं की भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा समीक्षा किए जाने को अनिवार्य बना दिया गया था। विनियामकों से संपदा प्रबन्धन सेवाओं के बारे में नये दिशानिर्देश तैयार करने के लिए भी कहा गया था।

बैंकिंग जगत की गतिविधियां

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने नियत लक्ष्य को पार किया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार द्वारा उसकी महत्वाकांक्षी योजना वित्तीय समावेशन के तहत उनके लिए निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गए हैं। वित्तीय वर्ष 2011 में सार्वजनिक क्षेत्र के 21 और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पांच सहयोगी बैंकों ने सामूहिक रूप से 26,630 गावों तक मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाईं, जो 23,629 गांवों के नियत लक्ष्य का 118 % है। सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर बैंकिंग सेवाओं के लाभ सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किए थे।

अप्रैल में ऋण वृद्धि धीमी पड़ी, जमा वृद्धि सपाट रही

बैंकों ने मंद मौसम में प्रवेश किया है, क्योंकि वित्तीय वर्ष के पहले महीने में ऋण वृद्धि मंद हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 22 अप्रैल को बैंके अग्रिम एक पखवाड़े पहले के स्तर से 37,407 करोड़ घट गए। आम तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले कुछेक महीनों में ऋण वृद्धि मंद पड़ जाती है, क्योंकि कारपोरेट निकाय अपनी लेखा-परीक्षा में व्यस्त हो जाते हैं तथा उसमें जुलाई - सितम्बर तिमाही में तेजी आने की आशा की जाती है। हालांकि, इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में अग्रिमों में 22 % की वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2010-11 में सार्वजनिक क्षेत्र के निवल ब्याजगत मार्जिन में अच्छी-खासी वृद्धि दर्ज हुई

सार्वजनिक क्षेत्र के कई एक बैंकों के निवल ब्याजगत मार्जिन (NIM) में 2010-11 में अच्छी वृद्धि परिलक्षित हुई, जिसका लाभप्रदता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। किसी बैंक के कार्य-निष्पादन का निर्धारण करने के एक मुख्य मापदंड - निवल ब्याजगत मार्जिन में वृद्धि के कारण कई एक और भिन्न-भिन्न हैं। जिन बैंकों ने अपने परिणाम घोषित कर दिए हैं, उनमें आन्ध्र बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH) और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सुदृढ़ वृद्धि परिलक्षित हुई, जबकि अन्य बैंकों में निवल ब्याजगत मार्जिन में ऊर्ध्वमुखी बदलाव अच्छी से साधारण श्रेणी में रहा।

सिंगापुर में इंडियन बैंक को उधार सम्बन्धी राहत

सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने इंडियन बैंक के लिए उधार देने की दृष्टि से अधिक राहत प्रदान करते हुए उसके परिसम्पत्ति अनुरक्षण अनुपात (AMR) को पूर्ववर्ती 90 % से घटा कर 50% कर दिया है। इंडियन बैंक, जो उस देश में पिछले 70 वर्षों से कार्यरत है, के पास 6,000 करोड़ रुपये की उत्कृष्ट ऋण-बही मौजूद है।

उधार दरों में वृद्धि से ऋण वृद्धि मंद हो जाएगी : बैंकर

प्राय: प्रत्येक बैंक द्वारा उधार दरों में कम से कम 50 आधार अंकों की वृद्धि किए जाने तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसकी आधार और न्यूनतम मूल उधार दरों (BPLR) में 75 आधार अंकों की भारी वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप बैंकरों का मानना है कि इस वर्ष में ऋण वृद्धि में कुछ मंदी आ सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसने मई के प्रारंभ में प्रमुख नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की वृद्धि की थी, ने वर्ष 2011-12 में 19 % की खाद्येतर ऋण वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि जमाराशियों में 17 % की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। जहां उनकी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था निरंतर अच्छे पायदान पर है, वहीं बैंकरों का कहना है कि खुदरा और कारपोरट, दोनों ही खण्डों में उधारकर्ताओं की ओर से कुछ हिचकिचाहट देखने में आ सकती है।

बैंकों से अशोध्य ऋणों से सम्बन्धित प्रावधानीकरण बढ़ाने हेतु कहा गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कुछेक प्रकार के अशोध्य एवं पुनर्संरचित ऋणों के समक्ष एक ऐसे उपाय के तौर पर विवेकसम्मत प्रावधान के रूप में अधिक निधियां अलग रखने के लिए कहा है, जो चूक जैसे आघातों के विरुद्ध कगार पर खड़े ऋणदाताओं की ऋण-बहियों को बचाने में सहायता करेगा, किन्तु जो उनके लाभों को प्रभावित कर सकता है,। ये प्रावधान उस प्रति-चक्रीय सुरक्षित भण्डार के अतिरिक्त होंगे, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणदाता बैंकों से उनके अशोध्य ऋणों को सुरक्षित करने के लिए 70 % की दर से प्रावधान करने के बाद अपनी अधिशेष निधियों से सृजित करने हेतु कहा है।

विनियामकों के कथन

ऊंची मुद्रास्फीति वृद्धि राह में खतरे उपस्थित कर रही है : डॉ. सुब्बाराव

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव का कहना है कि मुद्रास्फीति का वर्तमान उच्च स्तर भावी वृद्धि के मार्ग में महत्वपूर्ण खतरे पैदा कर रहा है और इसे अल्पावधिक दृष्टि से वृद्धि का कुछ स्तर तक त्याग करते हुए भी कम किया जाना आवश्यक है। मुद्रास्फीति पर अंतर-मंत्रिस्तरीय समूह (IMG) के समक्ष किए गए एक प्रस्तुतिकरण में डॉ. सुब्बाराव ने कहा कि वर्ष 2011-12 के बैंक के वार्षिक वक्तव्य में घोषित मौद्रिक नीति सम्बन्धी उपाय इस मान्यता पर आधारित थे कि अल्पावधिक दृष्टि से कुछ हद तक वृद्धि की कीमत पर भी मुद्रास्फीति को कम किए जाने वाले उपायों को प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए। अंतर-मंत्रिस्तरीय समूह (IMG) का गठन स्फीतिकारी स्थिति की समीक्षा करने और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए फरवरी में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सुझाव पर किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अन्तर्निहित प्रतिभूति के रूप में 2, 5 वर्षीय जिल्ट वायदा सौदों पर विचार

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि "भारतीय रिज़र्व बैंक अन्तर्निहित प्रतिभूति के रूप में 2 वर्षीय और 5 वर्षीय सरकारी बॉण्डों के साथ वायदा संविदाएं आरंभ करने पर विचार कर रहा है। ऋण चूक अदला-बदली (swaps) से सम्बन्धित मानदंड शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। ऋण चूकों पर दिशानिर्देशों के प्रारूप को फरवरी में हमारी वेबसाइट पर डाला गया था तथा हमें उन दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में भारी मात्रा में प्रति-सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। हमने उन दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में कुछ विचार-विमर्श किया है तथा हम इनके बहुत जल्दी ही जारी किए जाने की आशा करते हैं।"

मौद्रिक प्रेषण अब भी उत्तम प्रथाओं से काफी दूर

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि मौद्रिक प्रेषणों में यद्यपि सुधार हो रहा है, तथापि वे अब भी उत्तम प्रथाओं से अच्छी-खासी दूरी पर हैं। प्रेषण प्रक्रिया को अवरुद्ध करने वाले कारक हैं : जमाकर्ताओं और बैंकों के बीच विषम सम्बन्ध; डाकघर बचतों पर नियंत्रित ब्याज दरें, जिनका विद्यमान ब्याज दर प्रवृत्ति के अनुरूप समायोजन नहीं किया जाता तथा वित्तीय बाज़ारों में मौजूद कठोरताएं। ये कारक मौद्रिक संकेतों की प्रभावशीलता को मंद कर देते हैं और भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यित प्रणाली के अंगीकरण को जटिल बना देते हैं। डॉ. सुब्बाराव यह मत व्यक्त करते हैं कि लोकतंत्र की अनिवार्यताओं और गरीबों की विशाल जनसंख्या को देखते हुए भारत में मौजूद किसी भी सरकार को मूल्य स्थिरता के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना होगा और वह वास्तव में संवेदनशील रही है, भले ही इसके कारण अल्पावधिक दृष्टि से परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न हों।

पोर्टफोलियो अन्तर्वाह चिंता के विषय हैं : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पोर्टफोलियो अन्तर्वाहों की गुणवत्ता पर आशंका व्यक्त करने के बावजूद देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की आशा लगा रखी है। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ का कहना है कि "भारत पूंजी अन्तर्वाहों को अवशोषित करने में इसलिए समर्थ हुआ है क्योंकि यहां चालू खाते के घाटे की स्थिति मौजूद है। किन्तु हम पोर्टफोलियो अन्तर्वाहों की गुणवत्ता के प्रति आशंकित हैं। आज हमें उस अर्थ में अत्यधिक अस्थिरता नहीं दिखाई देती। हम चाहेंगे कि देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो, ताकि अन्तर्वाहों की गुणवत्ता परिवर्तित हो।" श्रीमती गोपीनाथ ने यह भी कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक नये बैंकिंग लाइसेंसों के सम्बन्ध में दिशानिर्देश कुछेक सप्ताहों में ही जारी कर देगा। "हम (दिशानिर्देशों के प्रारूप के सम्बन्ध में) सरकार के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। वैसे सरकार के साथ किसी प्रकार का टकराव नहीं है। इन दिशानिर्देशों के बारे में हमारे विचार समान ही हैं।"

कीमते वर्तमान स्तर से अधिक नहीं बढ़ सकतीं : डॉ. गोकर्ण

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि कीमते वर्तमान स्तर से बहुत अधिक नहीं बढ़ सकतीं, किनु उनके वर्तमान स्तर से कम होने के अवसर भी कम हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबाव अब भी बने हुए हैं। डॉ. गोकर्ण का कहना है कि "नीति निर्धारण में मुद्रास्फीति एक प्रबल चिंता वाला कारक है। खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की ऊंची कीमत से यह पता चलता है कि निर्माता निविष्टि लागत को ग्राहकों पर डाल सकते हैं। प्रणाली में पर्याप्त मांग मौजूद है और इसलिए जिंसों की कीमतों में वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति का रूप ले सकती है।

'स्थिर, उच्च वृद्धि के लिए कम मुद्रास्फीति अनिवार्य'

भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अल्पावधिक स्वरूप वाली वृद्धि का त्याग करना पड़ सकता है। शीर्ष बैंक के अनुसार स्थिर वृद्धि के लिए कमतर मुद्रास्फीति आवश्यक होती है। मुद्रास्फति, जो वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं से उच्चतर स्तर पर बनी रही, अप्रैल में 8.66 % के स्तर पर थी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार हाल के दिनों में ईंधन की कीमतों में हुई भारी वृद्धि से स्फीतिकारी दबावों के और बढ़ने की आशा है।

नीतिगत पैनल के गठन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को कानूनी स्वायत्तता आवश्यक : डॉ. सुब्बाराव

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने इस बात पर बल दिया है कि शीर्ष बैंक को संयुक्त राज्य अमेरिका की फेडरल ओपेन मार्केट कमिटी के अनुरूप मौद्रिक नीति समिति के गठन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किन्तु यह कार्य कुछेक शर्तों के तहत किया जाना चाहिए। डॉ. सुब्बाराव का कहना है कि एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, किन्तु केन्द्रीय बैंक का 'कानूनी तौर पर समर्थित □□' इसकी एक आवश्यक पूर्व-शर्त है। डॉ. सुब्बाराव का कहना है कि "मेरे विचार से हमें मौद्रिक नीति समिति गठित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किन्तु चरणबद्ध विधि से। ये कुछेक पूर्व-शर्तें हैं। प्रारंभिक तौर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को कानूनी विधि से समर्थित स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।"

मुद्रास्फीति का लक्ष्यांकन उचित नहीं : भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि भारतीय रज़र्व बैंक, जिसने दरों में 50 आधार अंकों की भारी वृद्धि की थी, अल्पावधिक दृष्टि से मुद्रास्फीति के लक्ष्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि कीमतों से सम्बन्धित दबाव प्राय: मांग प्रेरित होते हैं। "भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्यांकन कतिपय कारणों से न तो व्यवहार्य है और न ही उचित। हमारे जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में शीर्ष बैंक के लिए यह व्यावहारिक नहीं है कि वह वृहत्तर विकासपरक संदर्भों को भूल कर अनन्य रूप से

मुद्रास्फीति पर ही ध्यान केन्द्रित रखे। भारत में मौद्रिक नीति के प्रेषण में सुधार हो रहा है, किन्तु वह अभी तक उत्तम प्रथाओं से काफी दूर है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने और अधिक मौद्रिक कठोरता के संकेत दिए

8.6 % की मुद्रास्फीति को अत्यधिक की संज्ञा देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि वह इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी समीक्षा बैठक में और अधिक नीतिगत कार्रवाई कर सकता है। उक्त बैठक 17 जून को होने वाली है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने निदेशक मंडल की उस बैठक के बाद जिसमें देश की मौद्रिक एवं वित्तीय घटनाओं की समीक्षा की गई, यह जानकारी दी।

भारतीय रिज़र्व बैंक : 4.6 % के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन

जब तक कि ईंधन एवं उर्वरक की कीमतों में हुई वृद्धि को हिसाब में लेने के लिए समायोजन नहीं किए जाते, भारतीय रिज़र्व बैंक को इस वर्ष राजकोषीय घाटे से सम्बन्धित अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बाज़ार में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि सरकार को इस अंतर को मिटाने के लिए उधारों में तेजी लानी पड़ सकती है। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) कई महीनों से दुराग्रहपूर्ण ढंग से उच्च बने हुए हैं तथा वे अप्रैल में वार्षिक आधार पर बढ़ कर 8.66 % पर पहुंच गए। ऊर्जा की अपेक्षाकृत अधिक कीमत की संभावना से भारतीय रिज़र्व बैंक पर जून में ब्याज दर बढ़ाने और कठोर रुख अपनाने का दबाव बढ़ेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक को मुद्रास्फीति के वर्ष के अंत तक घट कर 6 % पर आने के पहले उसके वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में अधिक बनी रहने की आशा है।

विदेशी मुद्रा विनिमय

1,00,000 डालर से अधिक के विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों के सौदों की रिपोर्टिंग अनिवार्य : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्य दल ने यह सिफारिश की है कि 1,00,000 डालर अथवा उससे अधिक मूल्य वाले व्युत्पन्नियों के सौदों - वायदा और अदला-बदली, दोनों ही की रिपोर्टिंग रिपोजिटरी के रूप में कार्यरत एजेन्सी को की जानी चाहिए। गोपनीयता के लिए ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा में काउंटर पर किए जाने वाले इस प्रकार के व्युत्पन्नी सौदों के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CICIL) को रिपोर्टिंग का मंच बनाया जाना चाहिए। उक्त दल श्री पी. कृष्णमूर्ति, मुख्य महा प्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

जून 2011 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.76100	0.7730	1.2640		

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.76100	0.773	1.264	1. 733	2.149
जीबीपी	1.59156	1.6520	2.1020	2.4810	2.7860
यूरो	2.09688	2.367	2.659	2.887	3.066
जापानी येन	0.56313	0.369	0.415	0.486	.585
कनाडाई डालर	1.92817	1.948	2.256	2.523	2.753
आस्ट्रेलियाई डालर	5.59250	5.260	5.400	5.640	5.760

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**20 मई 2011 के दिन**	**20 मई 2011 के दिन**
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	**2**	**3**
कुल प्रारक्षित निधियां	13, 84, 939	308.534
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	12, 45, 467	277,202
ख) सोना	1, 05, 582	23, 790
ग) विशेष आहरण अधिकार	20, 602	4, 585
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	13, 288	2, 957

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

सूक्ष्मवित्त

गरीबों को उधार देने के लिए सूक्ष्मवित्त बैंक

गरीब लोग शीघ्र ही अनन्य रूप से एक "सूक्ष्मवित्त बैंक" से यथोचित ब्याज दर पर धनराशि उधार लेने में समर्थ हो जाएंगे। भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा पांच बैंकों का एक संघ सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के मुकाबले गरीबों को निधियों का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रथम अनन्य रूप से सूक्ष्मवित्त बैंक का गठन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रस्तावित बैंक का संभाव्यता अध्ययन लगभग पूरा हो गया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन सहित इस प्रक्रिया के जून में पूरी कर लिए जाने की संभावना है।

सूक्ष्म वित्त संस्था के ऋण की पुनर्व्यवस्था के लिए वैयक्तिक गारंटी अनिवार्य

कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था (CDR) कक्ष ने सूक्ष्म ऋणदाताओं के प्रवर्तकों के लिए ऋणों पर वैयक्तिक गारंटी अनिवार्य कर दिया है। ऋण पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम को 6 जून तक अंतिम रूप दे दिया जाना होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसकी समय -सीमा बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। इस नयी अपेक्षा ने इस आशय का भय निर्मित कर दिया है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ऋणों को पुनर्व्यवस्थित किए जाने के प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इन कम्पनियों के प्रवर्तकों ने इस मुहिम का प्रबलता के साथ विरोध किया था। बैंकों द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को उधार दिए गए 18, 000 करोड़ रुपये का लगभग एक तिहाई हिस्सा पुनर्व्यवस्था के लिए लिया जा चुका है। विश्लेषकों को यह भय है कि यदि पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम सफल नहीं होता, तो बैंकों के तुलन पत्रों के अनर्जक आस्ति ऋणों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हो जाएगी।

पण्य (जिंस) बाज़ार

जिंसें लगातार 5वें माह की सर्वाधिक लम्बी अवधि तक वित्तीय आस्तियों से आगे

विस्तृत होती अर्थव्यवस्थाओं तथा फेडरल रिज़र्व से वृद्धि को बढ़ावा देने की आश्वस्ति के फलस्वरूप कच्चे माल की मांग में बढ़ोत्तरी के कारण जिंसों ने शेयरों, बॉण्डों और डालर को लगातार पांचवें माह - कम से कम 14 वर्षों में सबसे लम्बी अवधि तकं पीछे छोड़ दिया। दि स्टैंडर्ड एण्ड पुअर की जीएससीआई - 24 वस्तुओं के कुल प्रतिलाभ सूचकांक में अक्तूबर 2008 से सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने

के बाद अप्रैल में 4.4 % की वृद्धि दर्ज हुई। विश्व के सभी देशों की इक्विटियों के सूचकांक एमएससीआई में 3.9 % की बढ़ोत्तरी हुई, जो दिसम्बर के बाद सर्वाधिक है और छ: प्रतिपक्षियों के समक्ष एक माप - अमरीकी डालर के सूचकांक में 3.9 % गिरावट दर्ज हुई, जो 33 माह के न्यून स्तर पर पहुंच गया। सभी प्रकार के बॉण्डों पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के वैश्विक व्यापक बाज़ार सूचकांक के आधार पर औसतन 3.9 % का प्रतिलाभ हुआ।

अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 12 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.8 % की वृद्धि संभव

वर्ष 2010-11 में 9% की अपेक्षाकृत त्वरित गति से वृद्धि दर्ज करने के बाद 2011-12 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के 8.8% रहने की आशा है। कृषि एवं संलग्न क्षेत्र में वर्ष 2010--2011 में अनुमानित 5.4 % की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2011-12 में 3.3 % की वृद्धि दर्ज होने की आशा है। 2011-12 में वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के अधिक बने रहने का अनुमान है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अर्थशास्त्री कीमतों के वृद्धि को प्रभावित करने के प्रति शंकालु

पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने अपस्फीति - एक ऐसी अवधि जिसमें आर्थिक वृद्धि मंद पड़ जाती है और कीमतें बढ़ती हैं - की आशंका व्यक्त की है - जिसके फलस्वरूप विगत दशक की समृद्धि के लाभ तिरोहित हो सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसंधान दल द्वारा जारी एक दस्तावेज़ में बताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के पिछले वर्ष की तुलना में मंद गति से बढ़ने के आसार हैं तथा मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहेगी। उक्त दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वृद्धि के प्रति जोखिमों के बने रहने के बावजूद नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

नयी नियुक्तियां

श्री अब्राहम चाको फेडरल बैंक के नये कार्यपालक निदेशक

श्री अब्राहम चाको को फेडरल बैंक के नये कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एम. डी. मल्या भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष निर्वाचित

भारतीय बैंक संघ की प्रबन्धन समति ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एम. डी. मल्या को वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है।

श्री अरुण बिसार्जा ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के मुख्य महा प्रबन्धक के रूप में कार्यभार संभाला

श्री अरुण बिसार्जा ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के मुख्य महा प्रबन्धक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व वे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, मुंबई में कार्यपालक निदेशक (मुख्य सतर्कता अधिकारी) थे।

श्री के. वेंकटरामन करूर वैश्या बैंक के नये प्रबन्ध निदेशक

अब तक एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री के वेंकटरामन 1 जून से करूर वैश्या बैंक के नये प्रबन्ध निदेशक होंगे।

सुश्री हंसिनी मेनन ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के मुख्य महा प्रबन्धक का कार्यभार संभाला

सुश्री हंसिनी मेनन ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के मुख्य महा प्रबन्धक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व वे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में मुख्य महा प्रबन्धक एवं महा प्रबन्धक थीं।

सिटी बैंक ने परिचालन प्रमुख की नियुक्ति की

सिटी बैंक ने श्री विक्रम सूद की नियुक्ति एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए परिचालन एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख के रूप में की है। श्री सूद क्षेत्र के 18 देशों में बैंक के परिचालनों, प्रौद्योगिकी और बैंक की साझी सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

श्री डी. के. मेहरोत्रा जीवन बीमा निगम के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त

श्री दिनेश कुमार मेहरोत्रा, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम को तीन माह अथवा आगामी आदेशों तक भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

श्री अशोक मोटवानी भारतीय स्टॉक धारिता निगम के प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त

श्री अशोक मोटवानी को भारतीय स्टॉक धारिता निगम (SHCIL) का प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री सी. हैंगो ने कैन फिन होम्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार संभाला

श्री सी. हैंगो ने 29 अप्रैल, 2011 को कैन फिन होम्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
आईडीबीआइई बैंक	भारतीय थल सेना	भारतीय थल सेना के साथ ऐसा समझौता ज्ञापन जिसके तहत बैंक अन्य बातों के साथ ही एटीएमों के नि:शुल्क उपयोग, सुरक्षित जमा लॉकरों के अधिमानी आबंटन, नि: शुल्क दुर्घटना बीमा, नि: शुल्क वित्तीय परामर्शी सेवाओं के साथ व्यापक श्रेणी वाली सेवाएं एवं उत्पाद तथा ग्राहकीकृत प्रतिरक्षा वेतन खाता सुविधा प्रदान करेगा।
भारतीय स्टेट बैंक	डीबोल्ड	भारतीय स्टेट बैंक ने अमरीका स्थित एक स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) प्रदाता डीबोल्ड के साथ स्टेट बैंक समूह की एटीएम विस्तार परियोजना के लिए एक करार हस्ताक्षरित किया है।
इंडसइंड बैंक	एचडीएफसी	इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बीच गृह ऋण वितरण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। इस करार के तहत इंडसइंड बैंक उसके द्वारा लाए गए गृह ऋणों को प्रवर्तित एवं वितरित करने हेतु अपनी 300 शाखाओं के नेटवर्क का उपयोग करेगा, कार्रवाई, संवितरण एवं शोधन से सम्बन्धित कार्य एचडीएफसी के पास रहेंगे। बैंक गृह ऋण के वितरण पर शुल्क-आधारित आय अर्जित करेगा।
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	एनएसडीसी	व्यावसायिक शिक्षा का वित्तीयन।

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

(पिछले अंक से जारी)

मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक की भूमिका को समझने के लिए पाठकों को सूचना उपलब्ध कराने के हमारे प्रयासों के एक अंग के रूप में हम "विजन" के पिछले कुछेक अंकों में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के विन्यास और कार्यों का समावेश करने के बाद इस अंक में वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति की एक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति (CGFS)

वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति (CGFS) वित्तीय बाज़ारों एवं प्रणालियों से सम्बन्धित व्यापक मुद्दों की निगरानी एवं जांच के लिए केन्द्रीय बैंकों का मंच है। यह मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता से सम्बन्धित उनके उत्तरदायित्वों को पूरा करने में केन्द्रीय बैंकों की सहायता करने हेतु उपयुक्त नीतिगत सिफारिशों को परिष्कृत करने में सहायता करता है। इस कार्य को करने में समिति वित्तीय बाज़ारों एवं वैश्विक वित्तीय प्रणाली को खतरों की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने तथा उन पर कार्रवाई करने में केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों की सहायता करने पर विशेष बल देती है।

सदस्यता

इसके सदस्य हैं केन्द्रीय बैंकों के उप गवर्नर, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक के आर्थिक सलाहकार। सदस्य संस्थाएं हैं : रिज़र्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया, नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, सेन्ट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, बैंक ऑफ कनाडा, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक, बैंक ऑफ फ्रांस, ड्यूश बण्डसबैंक, हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक ऑफ इटली, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ कोरिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ लक्जेमबर्ग, बैंक ऑफ मैक्सिको, नीदरलैंड्स बैंक, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, बैंक ऑफ स्पेन, स्वरिजेस रिक्सबैंक, स्विस नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिज़र्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयार्क।

अध्यक्ष

श्री मार्क कार्नी, गवर्नर, बैंक ऑफ कनाडा

बैठकों की आवधिकता

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक के सदस्य केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की द्विमासिक चार बैठकों के अवसर पर समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

रिपोर्टिंग व्यवस्था

जनवरी 2010 में की गई व्यवस्था के अनुसार वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति (CGFS) के अध्यक्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था बैठक में रिपोर्ट करते हैं, जिसमें वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति (CGFS) के निगरानी सम्बन्धी विचार विमर्शों और समिति की अन्य पहलकदमियों पर 31 केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों का समावेश है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करना (Mark to Market)

बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करना (Mark to Market) खातों के उचित मूल्य का वह माप होता है जो कुछ समय के बाद बदल सकता है, जैसे आस्तियां एवं देयताएं। बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करने (Mark to Market) का उद्देश्य किसी संस्था या कम्पनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति का यथार्थपरक मूल्यांकन उपलब्ध कराना होता है। किसी प्रतिभूति, पोर्टफोलियो अथवा खाते का उसके बही मूल्य के बजाय उसके बाजार मूल्य का प्रतिबिंबन करने हेतु उसकी कीमत या मूल्य को रिकार्ड करने का लेखांकन कार्य।

शब्दावली

ऋण चूक अदला-बदली (CDS)

ऋण अदला-बदली का खरीदार ऋण संरक्षण प्राप्त करता है, जबकि अदला-बदली का विक्रेता उत्पाद की ऋणपात्रता की गारंटी देता है। ऐसा करने से चूक का जोखिम नियत आय वाली प्रतिभूति के धारक से अदला-बदली के विक्रेता को अंतरित हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी ऋण अदला-बदली के खरीदार को बॉण्ड के कूपन भुगतान में चूक होने पर अदला-बदली के विक्रेता द्वारा बॉण्ड के सम मूल्य का पात्र बनाया जाएगा।

आईआईबीएफ की गतिविधियां

पीएनजी इंस्टिटयूट आफ बैंकिंग एण्ड बिजिनेस मैनेजमेंट में परामर्शी कार्य

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स ने पीएनजी इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड बिजिनेस मैनेजमेंट में सक्षमता आधारित दृष्टिकोण लागू करते हुए वर्तमान डिप्लोमा का पुनरीक्षण करने और

खण्डों को आशोधित एवं सुधारने से सम्बन्धित परामर्शी कार्य हाथ में लिया है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नेतृत्व वाले एक दो सदस्यीय दल ने उनके डिप्लोमा पाठ्यक्रम के ढांचे का अध्ययन करने तथा उसे समझने एवं डिप्लोमा की प्रासंगिकता पर पीएनजी बैंकिंग समुदाय की प्रति-सूचना प्राप्त करने के लिए 23 मई से 28 मई तक पापुआ न्यू गुएना का दौरा किया। परामर्शी कार्य का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है तथा शेष परामर्शी कार्य के 3-4 माह के भीतर पूरा कर लिए जाने और उसे सौंप दिए जाने की आशा है।

- भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या एमआर/ तक/ डब्ल्यूपीपी-15 / दक्षिण / 2010 - 12 मुंबई
- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

नेशनल बैंकिंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के लिए आस्ति देयता प्रबन्धन पर कार्यक्रम

संस्थान ने राष्ट्रीय बैंकिंग प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से काठमांडू में बैंकरों के लिए आस्ति देयता प्रबन्धन पर 30/05/2011 से 31/05/2011 तक एक द्विदवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया।

संस्थान समाचार

डीबीएफ पाठ्यक्रम हेतु पात्रता मानदंडों में छूट

दिसम्बर 2011 और उसके बाद वाली परीक्षाओं से बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा ऐसे नये अभ्यर्थियों के लिए मुक्त होगा, जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी है।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

7.60
7.40
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
5.80
02/05/11 03/05/11 04/05/11 06/05/11 09/05/11 10/05/11 123/05/11
14/05/11 18/05/11 20/05/11

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अप्रैल, 2011

- मांग दरें 6.41 और 7.41 के बीच मंडराती रहीं।
- माह के मध्य में सहज चलनिधि की स्थिति परिलक्षित।
- अंतिस्सप्ताह में चलनिधि कम होती दिखाई पड़ी।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

77
72
67
62
57
52
47
42

02/05/11 04/05/11 06/05/11 10/05/11 12/05/11 16/05/11 18/05/11
20/05/11 25/05/11 27/05/11

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- माह के पहले दिन ऐसा लगा कि प्रति डालर 43.90 निर्णायक रूप से टूटने के पहले कुछ और समय तक स्थिर रहेगा। बढ़ते चालू घाटे के साथ तेल और जिंसों की बढ़ती कीमतें भी डालर -रुपया युग्म पर दबाव डाल रही हैं।
- पिछले सप्ताह शुक्रवार 06-05-11 को 44.78/79 पर बंद हो कर रुपया असथिर बना रहा। रुपये की कमजोरी कमजोर शेयर बाज़ार, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों तथा वैश्वक स्तर पर डालर की शक्ति में निहित है।
- स्थानीय बॉण्डों पर सापेक्ष प्रतिफल निवेश बढ़ाने हेतु विदेशी निधियों में वृद्ध करेगा, इस आशय की बढ़ती अटकलबाजियों पर दो माह के कम स्तर से ऊपर उठते हुए रुपये का मूल्य बढ़ा। बुधवार 16 मई को रुपया 0.2 % बढ़ कर 45.055 प्रति डालर हो गया।
-आयातकों द्वारा डालर की चाह की आशा में रुपया लुढ़का। 20वीं को रुपया पुन: 0.1 % बढ़ कर 45. 0150 प्रति डालर हो गया।
- माह के दौरान यूरो में 1.78 % की मामूली गिरावट आई।
- मई के दौरान स्टर्लिंग पौंड 0.55 % बढ़ा।
- जापानी येन भी 0.55 % बढ़ा।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

18600
18500
18400
18300
18200
18100
18000
17900
17800

03/05/11 04/05/11 05/05/11 06/05/11 12/05/11 16/05/11 17/05/11 20/05/11 23/05/11 25/05/11 27/05/11

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जून, 2011